नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

7500 करोड़ खर्च, मेट्रो खड़ी

इंदौर में राजनीतिक खींचतान के चलते आम जनता सुविधा से वंचित

नवभारत न्यूज

इंदौर, 2 सितंबर. मध्य प्रदेश मेट्रो की इंदौर में 17 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन का निर्माण कार्य छह माह पहले पूरा हो चुका है. इसके निर्माण पर करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इसके बावजूद इंदौर मेट्रो धूल खा रही है.

वजह यह है कि राजनीतिक खींचतान में मेट्रो के दूसरे चरण का लोकार्पण नहीं हो रहा है. लोकार्पण नहीं होने के कारण आम जनता मेट्रो रेल की सुविधा से वंचित है. खास बात यह है कि मेट्रो के रख रखाव पर तैनात करीब 175 लोगों से ज्यादा का अमला बिना काम किए वेतन भत्ते ले रहा है. मध्यप्रदेश मेट्रो ने मई 2023 में मेट्रो की ट्रायल ली थी. इसके तीन सालों में मेट्रो की 17 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन का काम पिछले फरवरी में पूरा हो चुका है. 17 किलोमीटर मेट्रो येलो लाइन

पर 16 स्टेशन है. सीएमआरएस ने 24 मार्च को मेट्रो रेल गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहे तक संचालन की अनुमति जारी कर दी थी. 24 जून को मेट्रो संचालन अनुमति का समय भी खत्म हो चुका है. इसके पहले गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर 5 स्टेशन तक मेट्रो रेल का संचालन शुरू भी किया गया था, लेकिन यात्री नहीं मिलने से बंद कर दी गई.

ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले छह महीने से मेट्रो यार्ड में खड़ी धूल खा रही है. मेट्रो के मेंटेनेंस पर 175 से 200 लोगों का स्टॉफ तैनात है. 175 से ज्यादा लोगों के वेतन का भुगतान सरकार के खजाने से किया जा रहा है. मेट्रो रेल अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक बिना काम के वेतन भत्ते ले रहे हैं. करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान मेट्रो रेल नहीं चलने से सरकार को हो रहा है.

लोकार्पण को लेकर सियासी खींचतान

इसी चर्चा है कि इंदौर मेट्रो के दूसरे चरण का लोकार्पण राजनीतिक खींचतान के कारण नहीं हो रहा है. राजनीतिक खींचतान का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है. 17 किलोमीटर हिस्से में शहर के 11 किलोमीटर का एरिया बड़ी और घनी आबादी बदला क्षेत्र है, जिसमें 7500 करोड़ रुपए खर्च करने बाद आम जनता मेट्रो रेल सुविधा से वंचित है. दूसरी ओर मेट्रो यार्ड में खड़ी धूल खा रही है, जिसका रखरखाव में भारी राशि खर्च हो रही, सो अलग.

> इंदौर शहर में 31 किलोमीटर लंबी येलो एलिवेटेड लाइन की रिंग में 17 किलोमीटर का हिस्सा दो चरणों में बन कर तैयार हो चुका है. लवकुश चौराहे से मालवीय नगर तक मीटर 11 किलोमीटर के हिस्से में मेट्रो को बड़ी संख्या में यात्रियों के मिलने की संभावना है, लेकिन तीन महीने अनुमति का समय बीत गया और इंदौर मेट्रो के अधिकारियों द्वारा फिर से अनुमति रिव्यू करने की कार्रवाई की है. यह बात अलग है कि सीएमआरएस से दोबारा अनुमति में ज्यादा समय नहीं लगता है.

बस-डंपर भिड़े, छह की मौत

रीवा-सीधी मार्ग पर भयानक हादसा, 20 घायल

नवभारत न्यूज

रीवा, 2 सितंबर. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर रीवा सीधी मार्ग स्थित बदबार स्टैंड के समीप एक अत्यंत दुखद सड़क दुर्घटना घटित हुई है। सीधी की ओर से आ रही पवन एक्सप्रेस बस और रीवा की ओर से आ रहे डंपर के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना गुढ़ थाना पुलिस को दी.सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया.दुर्घटना में घायल हुए लगभग 20 लोगों को तत्काल एम्बुलेंस एवं अन्य वाहनों के माध्यम से उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल रीवा भिजवाया गया है. ?प्राथमिक सूचना के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में लगभग आधा दर्जन लोगों की मृत्यु हो चुकी है.घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता के साथ जारी है तथा प्रशासन द्वारा घायलों के समुचित इलाज और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

8 लाख का बैग चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार

इंदौर. बैंक से लोन के 8 लाख रुपए लेकर घर पहुंचे व्यक्ति का रुपयों से भरा बैग लिफ्ट में छूट गया था. वापस लौटने पर बैग गायब मिला. राऊ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की और उसके कब्जे से चोरी के पूरे 8 लाख रुपए बरामद कर लिए.

सामाजिक न्याय के टेंडर में 'घर का मुकाबला'

- **जीएम पोर्टल पर चार फर्मों ने आपस में दिखाई फर्जी प्रतिस्पर्धा 10.99 करोड़ का घोटाला उजागर**
- **3,754 रुपए का यूपीएस 11,247 में बेचा, ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर**

नवभारत न्यूज

भोपाल, 2 सितंबर. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में वर्ष 2024 में हुई करीब 10.99 करोड़ रुपए की कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस की खरीद में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है.

जांच में सामने आया कि जीएम पोर्टल पर अलग-अलग फर्मों के नाम से आपस में प्रतिस्पर्धा दिखाकर टेंडर हासिल किया गया, जबकि इन फर्मों के बीच आपसी, पारिवारिक संबंध था. इतना ही नहीं, विभाग को पुराने कंप्यूटरों को नया बताकर देने, निर्धारित ब्रांड के स्थान पर स्थानीय कंपनी की एसएसडी लगाने और बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध यूपीएस को कई गुना अधिक कीमत पर बेचने के आरोप भी सामने आए हैं. जांच में यूपीएस की खरीद में भी बड़ा अंतर सामने आया. जीएम पोर्टल पर संबंधित यूपीएस 3,754 रुपए में उपलब्ध था, जबकि विभाग ने इसके लिए 11,247 रुपए का भुगतान किया. मामले में मेसर्स साईबाबा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रणधीर कुमार पटेल, मेसर्स शांति ट्रेडर्स की हेमलता पटेल, मेसर्स एचटीएम इंडिया के अशोक कुमार सिंह, मेसर्स सूरज इंटरप्राइजेज के देवेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया है.

जांच में कंप्यूटरों को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई. विभाग को दिए गए कंप्यूटरों के वारंटी रिकॉर्ड में उनकी इंस्टॉल होने की तारीख 22 जुलाई 2024 दर्ज थी, जबकि विभाग का टेंडर 23 सितंबर 2024 का था. पहले से इस्तेमाल कंप्यूटरों को नया बताकर सप्लाई किया गया.

फर्मों के एक ही मोबाइल नंबर और कार्यालय का पता

जांच में जीएसटी रिकॉर्ड में मेसर्स शांति ट्रेडर्स का मोबाइल नंबर वही मिला, जो साईबाबा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रिकॉर्ड में दर्ज था. एचटीएम इंडिया की ई-मेल आईडी भी साईबाबा कंपनी के नाम से जुड़ी मिली. एचटीएम इंडिया ने एमपी नगर में जो कार्यालय पता दर्ज कराया था, वह साईबाबा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पते से भी जुड़ा मिला. संबंधित मोबाइल नंबर के दस्तावेजों में रणधीर कुमार पटेल का नाम और आधार कार्ड दर्ज पाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि चारों फर्में जीएम पोर्टल के कई अन्य टेंडरों में भी साथ-साथ बोली लगाती रही हैं. उनकी बोली की कीमतें कई बार एक-दूसरे के करीब रहीं और टेंडर बारी-बारी से इन्हीं फर्मों को मिलते रहे.

एक नजर में

132 केवी लाइन रोकने की कोशिश नाकाम

जबलपुर। हाईकोर्ट ने मंडीदीप की 417.96 करोड़ निवेश वाली नाहर परियोजना के लिए प्रस्तावित 132 केवी डीसीएसएस मंडीदीप-नाहर ट्रांसमिशन लाइन को रोकने की कोशिशों को नाकाम करते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं निरस्त कर दीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि नाहर पाली फिल्म्स लिमिटेड को देने के निर्देश दिए। मामले में दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने ट्रांसमिशन लाइन के वर्तमान मार्ग को चुनौती देते हुए उसे बदलने और निर्माण कार्य रोकने की मांग की थी। नाहर पाली फिल्म्स लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपराह ने पक्ष रखा, जबकि एमपीपीटीसीएल की ओर से अधिवक्ता एसपी मिश्र उपस्थित हुए। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग को तकनीकी विशेषज्ञ पहले ही सुरक्षा कारणों से अस्वीकार कर चुके थे। प्रस्तावित मार्ग गैस पाइपलाइन के लिए निर्धारित सुरक्षा दूरी का उल्लंघन करता था।

गुस्ताखी माफ

शिक्षक को बताया वकील

हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

शिक्षा विभाग, जेल प्रशासन और स्टेट बार काउंसिल से 30 दिन में रिपोर्ट तलब

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 2 सितंबर. हाईकोर्ट ने फर्जी वकालतनामे और शपथपत्र में कथित रूप से गलत जानकारी देने के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने पाया कि जिस नीरज कुमार साकेत को अधिवक्ता बताया गया था, वह वास्तव में रीवा जिले के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के गेस्ट लेक्चरर, ग्रेड टू के पद पर कार्यरत हैं.

कोर्ट ने अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के शपथपत्र में नीरज साकेत को अधिवक्ता बताए जाने को प्रथमदृष्टया गलत जानकारी माना. हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग, रीवा सेंट्रल जेल प्रशासन व एमपी स्टेट बार काउंसिल को अलग-अलग जांच कर 30 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई में यह भी सामने आया कि नीरज साकेत ने राम प्रकाश यादव के लिए कई वकालतनामे प्राप्त किए थे. कोर्ट ने कहा कि यदि उनका किसी आरोपित से पारिवारिक संबंध भी हो, तो अन्य आरोपितों के वकालतनामा प्राप्त करने का अधिकार नहीं बनता. कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार रीवा सेंट्रल जेल से अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के लिए 300 से अधिक वकालतनामे प्राप्त किए गए. हाईकोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए. रीवा जेल के तत्कालीन अधीक्षक की भूमिका की भी जांच होगी.

हर सप्ताह देना होगा जिले के कामों का ब्यौरा

जन विश्वास पोर्टल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया लांच

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 सितंबर. जिलो के मैदानी अफसरों को अब अपने कामों का ब्यौरा हर सप्ताह देना होगा. एक सप्ताह की अवधि में उन्होंने कहां दौरा किया, किस समस्या से रूबरू हुए और उसके निराकरण के लिए क्या किया.

शिकायतों का निराकरण हुआ भी या नहीं? लोगों से कहां और कैसे संवाद किया, किन विषयों को लेकर बैठक की और जिले में वे किस तरह का नवाचार कर रहे हैं. ये सब ब्यौरा उन्हें देना होगा. इसके लिए बुधवार को जन विश्वास पोर्टल लांच कर दिया है. ये पोर्टल अब अफसरों के लिए किसी आईने की तरह होगा, जिसे खोलते ही उनके कामों का पूरा लेखा-जोखा सामने होगा. अभियान के दौरान शुक्रवार तक किए गए कार्यों का ब्यौरा कलेक्टरों को हर हाल में सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संभागायुक्तों की होगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पोर्टल को मंत्रालय में लांच किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 अगस्त से आरंभ मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अब तक चार सप्ताह सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं. कम समय में ही अभियान का अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव रहा है. जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सभी सप्ताह में एक दिन फील्ड पर जाकर जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण कर रहे हैं. जनविश्वास पोर्टल, अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी और लाभकारी सिद्ध होगा. प्रत्येक स्तर पर अधिकारी इस पोर्टल में यूजर मैनुअल के अनुसार नियमित रूप से जानकारियां अपलोड करना सुनिश्चित करें. इसके समेकित उपयोग से मैदानी स्तर पर जनसामान्य को बहुत लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास अभियान के तहत किए जा रहे कार्यो की संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल बनाया गया है. पोर्टल पर अभियान के तहत किए गए भ्रमण, निरीक्षण, जन संवाद, उद्यम संवाद, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक, नीतिगत विषय, अभियान के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों, जिले के प्रमुख नवाचारों और जिले की ओर से भेजे जाने वाले सुझावों को दर्ज किया जाएगा.

देश की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मर यूनिट का शुभारंभ आज

- **सीएम करेंगे लोकार्पण, 50 एकड़ में फैला है प्लांट**

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी (क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स) पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पॉवर ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफॉर्मर के रोल-आउट का शुभारंभ करेंगे.

करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पॉवर ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण सुविधा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि-पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहां उत्पादन प्रारंभ हो गया है.

सीहोर में स्थापित यह आधुनिक इकाई देश में बढ़ती विद्युत जरूरतों को देखते हुए उच्च क्षमता वाले पॉवर ट्रांसफॉर्मर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पॉवर ट्रांसफॉर्मर बनाए जाएंगे. इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पॉवर ट्रांसफॉर्मर तैयार करने की होगी. इतनी बड़ी क्षमता वाली सुविधा एक ही स्थान पर स्थापित होने से देश में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण को मजबूती मिलेगी.

सीहोर में तैयार होने वाले उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर देश के विभिन्न हिस्सों के साथ वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचेंगे. इकाई में तैयार होने वाले ट्रांसफॉर्मर विद्युत क्षेत्र के साथ डेटा सेंटर, रेलवे, नवकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस तथा ट्रांसमिशन अधोसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं में उपयोग किए जाएंगे.

सीजी की इस इकाई से सीहोर में 2000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करीब नौ दशकों से कार्य कर रही है. कंपनी ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर, इंडक्शन मोटर्स, ड्राइव्स, ट्रैक्शन मोटर्स और अन्य विद्युत उपकरणों का निर्माण करती है. सीहोर की नई इकाई कंपनी की पॉवर ट्रांसफॉर्मर निर्माण क्षमता को बड़े स्तर पर विस्तार देगी.

भारत की जीडीपी को विश्व बैंक ने सराहा

अध्यक्ष बंगा ने कहा कि 8 फीसद से ज्यादा की क्षमता

नई दिल्ली, 2 सितंबर. भारत में मौजूदा 7-8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर से भी अधिक तेजी से बढ़ने की क्षमता है. विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापारिक अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद भारत के हालिया आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया.

प्रतिशत 20 वित्त मंत्रियों की बैठक से इतर बातचीत में बंगा ने कहा कि भारत लगातार 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रहा है, जो काफी अच्छा प्रदर्शन है और देश के लिए इससे आगे बढ़ने की भी संभावना है. उन्होंने कहा कि भारत की 7.8 प्रतिशत की हालिया वृद्धि में सेवाओं और निर्यात का अच्छा योगदान रहा है. इसके अलावा निवेश भी मजबूत बना हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है.

बंगा के अनुसार भारत सड़क, पुल, हवाई अड्डे, बिजली, पानी और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है. हालांकि, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी आगे सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत के स्किलिंग और शिक्षा तंत्र को भविष्य में पैदा होने वाली नौकरियों तथा निजी क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप और बेहतर तरीके से तैयार करना होगा.

नियामकीय सुधारों के संदर्भ में बंगा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल में किए गए श्रम कानूनों में बदलाव का उल्लेख किया.

> **रोजगार और युवाओं के अवसरों पर जोर**
>
> बंगा ने कहा कि आर्थिक वृद्धि का आकलन केवल किसी एक तिमाही के आंकड़ों से नहीं होना चाहिए. महत्वपूर्ण यह है कि इस वृद्धि को रोजगार और युवाओं के लिए अवसरों में बदला जाए. उन्होंने रोजगार सृजन के लिए तीन प्रमुख स्तंभ बताए भौतिक और मानव बुनियादी ढांचा, नियामकीय सुधार और निजी पूंजी का इस्तेमाल.

आमने-सामने भिड़े बस और मिनी ट्रक, 30 यात्रियों की बची जान

गुना. गुना और अशोकनगर जिले की सीमा पर स्थित सिंध नदी के पुल पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ब्रेक फेल हो जाने के कारण यात्रियों से भरी एक बस सामने से आ रहे मिनी ट्रक से जा भिड़ी. गनीमत यह रही कि दोनों वाहनों की गति धीमी थी, जिससे वे पुल की रेलिंग तोड़कर 80 फीट गहरी नदी में नहीं गिरे और बड़ा हादसा टल गया. इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है. घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की है. बालाजी ट्रेवल्स की बस करीब 30 यात्रियों को लेकर गुना से अशोकनगर की ओर जा रही थी. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे मिनी ट्रक से सिंध नदी के पुल के बीचों-बीच उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई.

पर्दाफाश देशभर की 212 साइबर ठगी से जुड़े तार, 151 फर्जी सिम की पहचान, दो गिरफ्तार

इंदौर बना साइबर ठगी का गेटवे, 15 राज्यों में फैला नेटवर्क

नवभारत न्यूज

इंदौर, 2 सितंबर. साइबर ठगों ने इंदौर को देशभर में फैले ऑनलाइन फ्रॉड के नेटवर्क का जरिया बना रखा है. क्राइम ब्रांच और पुलिस की तकनीकी जांच में ऐसे बैंक खाते और मोबाइल सिम सामने आए हैं, जिनके तार देश के 15 राज्यों में दर्ज साइबर ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मिले हैं.

एक मामले में इंदौर के 25 वर्षीय युवक का बैंक खाता 15 राज्यों की साइबर ठगी से जुड़ा मिला, जबकि दूसरे मामले में शहर के संदिग्ध सिम विक्रताओं और पीओएस धारकों से जुड़ी 151 सिम

का इस्तेमाल 212 साइबर ठगी में सामने आया है. पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी संदिग्धों की तलाश की जा रही है. ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी में इस्तेमाल संदिग्ध बैंक खाते का पता लगाया. राज्य साइबर पुलिस से मिले डेटा की जांच में यह 15 राज्यों में दर्ज हुई ठगी की एफआईआर वाला खाता श्री गणेश नगर, इंदौर अभिषेक तिवारी (25), निवासी के नाम पर मिला. पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड और खाते से हुए लेन-देन का एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों से मिलान किया. जांच में अभिषेक का खाता दिल्ली, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों की साइबर ठगी से खाते का कनेक्शन सामने आया. खाते में करीब डेढ़ करोड़ रुपए का लेन-देन मिलने की बात भी सामने आई है. अभिषेक को गिरफ्तार कर अब खाते का वास्तविक उपयोगकर्ता, संदिग्ध लेन-देन और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.

पुलिस के अनुसार एक सिम 200 रुपए में आगे दी गई और बाद में करीब 500 रुपए में दूसरे व्यक्ति को सौंप दी गई. आरोपी फर्जी सिम से लोगों को फोन कर कम कीमत में थोक जींस-पैंट उपलब्ध कराने और फ्रेंचाइजी देने का झांसा देते थे. इस मामले में राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भगवानदास उर्फ नाना जुनवाल, हिमांशु उर्फ रोहित जुनवाल और आशीष शर्मा की तलाश जारी है. पुलिस अब दोनों मामलों में मोबाइल नंबर, बैंक खातों, सिम की खरीद-बिक्री और देशभर में दर्ज शिकायतों के बीच कड़ियों की जांच कर रही है.

151 फर्जी सिम, 212 शिकायतों से कनेक्शन

दूसरे मामले में ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत आई-4-सी के डेटा की तस्दीक में इंदौर के 49 संदिग्ध सिम विक्रेताओं और पीओएस धारकों से जुड़ी 151 सिम सामने आईं. इन सिम का इस्तेमाल देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज 212 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों में पाया गया.

प्रसूता की मौत के बाद अधीक्षक को हटाया

नवभारत न्यूज

रीवा, 2 सितंबर. रीवा के गांधी मेमोरियल चिकित्सालय में गर्भवती कल्पना मिश्रा और उसके नवजात की मौत के 7 दिन बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.

अधीक्षक पद की जिम्मेदारी सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. प्रियंक शर्मा को सौंपी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार की देर रात इसका आदेश जारी किया.

कल्पना मिश्रा से जुड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो भी वायरल हुआ था इसमें गर्भवती मदद की गुहार लगाते हुए कहती सुनाई दे रही थी, ये लोग मुझे मार डालेंगे. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में प्रसूता की स्थिति और उसे मिल रहे उपचार पर गंभीर सवाल उठे थे और दो महिला डॉक्टर के साथ दो नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था. जीतू पटवारी ने अस्पताल अधीक्षक के बयान का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि वे डिप्टी सीएम के करीबी हैं, इसलिए कार्रवाई से बचे हुए हैं. देर रात अधीक्षक को हटाने की कार्रवाई हुई. मिश्रा और उसके नवजात की मौत के मामले में उपचार, डॉक्टरों की ड्यूटी, अस्पताल प्रशासन के रवैये और परिजनों से बातचीत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे. मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की गई थी. समिति अस्पताल पहुंचकर दस्तावेज और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर चुकी है.

परिजन बैठे आमरण अनशन पर तब हुई कार्रवाई

जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजन आक्रोशित थे और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई थी लेकिन अब परिजन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए सिरमौर चौराहे के पास स्थित तानसेन काम्प्लेक्स के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए है मृतका के पिता रामशिरोमणि मिश्र और परिजन अनशन पर सुबह बैठ गए है रिमझिम बारिश के बीच अनशन चल रहा है एक दिन पूर्व अनशन पर बैठने की जानकारी कलेक्टर को ज्ञापन सौप कर दी गई थी.